Difficulties in Rail Transport of Bananas in Maharashtra

*173. DR. A. U. AZMI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railways have increased the tariff and reduced the wagon supply to the banana growers in Maharashtra thereby forcing the traders and growers to send their goods through trucks causing tremendous loss of revenue to the Railways;

(b) if so, reasons thereof; and

(c) steps taken to ease the situation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c). A general increase in parcel rates, including that of bananas, was effected from 1-4-1982 as approved by the Parliament. This was based on the recommendation of Rail Tariff Enquiry Committee. However, a 40 per cent concession over normal tariff rate has been extended to this traffic moving in wagon loads from Bhusaval Division of the Central Railway. The demand of the trade for supply of wagons is met in full.

डा ए० यू० आजमी : बनाना की कीमत डिपेंड करती है उसे पैदा करने के खर्च पर और उसे सप्लाई करने के खर्च पर । जनता पीरियड में बनाना ग्रोअर्स को एक वैगन के किराये में 50 परसेंट कनसेशन दिया गया था । हमारी सरकार ने उस कनसेशन को कम कर के 30 परसेंट कर दिया । आज मिनिस्टर साहब ने अपने जबाब में कहा है कि उसे बढ़ा कर 40 परसेंट कर दिया गया है । इसके अलावा एक वैगन का किराया 3215 रुपया से बढ़ा कर 4250 रुपए कर दिया गया । इसक नतीजे के तौर पर दोहरा घाटा हुआ । चूंकि लोगों ने बनाना रेल के बजाए ट्रकों से ले जाना शुरु कर दिया, इस लिए रेलवे को घाटा हुआ । दूसरे, पब्लिक को महंगा केला खरीदना पड़ा है । मेरा सवाल यह है कि क्या कनसेशन को 40 परसेंट से बढ़ा कर 50 परसेंट किया जाएगा या नहीं । दूसरे, जो वैगन का रेट बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से रेलवे और पब्लिक दोनों सफर कर रहे हैं, क्या उसको रिवाइज कर के ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे कि बनाना रेलवे से सप्लाई कराया जा सके ?

श्री मल्लिकार्जुन : रेट में परिवर्तन तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए बजट में सदन की अनुमति ली गई है । कनसेशन 40 परसेंट से 50 परसेंट नहीं हो सकता । जहां तक रेल डिब्बों की बात है, जून में 244 डिब्बों की मांग हुई और 244 डिब्बे सप्लाई किए गए । अगस्त में 1538 डिब्बों की मांग की गई और 1271 डिब्बों की सप्लाई की गई । 182 डिब्बे कैंसिल किए गए हैं । सितम्बर में तकरीबन 4989 डिब्बों की मांग की गई, 4600 सप्लाई किए गए और 388 कैंसिल किए गए हैं ।

डा० ए० यू० आजमी : जहां तक वैगन प्रोवाइड करने का सवाल है, जहां तक मुझे मालूम है यह हुआ नहीं है । लेकिन जबाब में कहा गया है कि हमने किया है उसमें फर्क है । लेकिन हम मान लेते हैं कि आपने वैगन की सप्लाई पूरी कर दी लेकिन बनाना के साथ साथ कन्ट्री को ग्रीन वेजिटेबल की भी जरूरत होती है और उसको पहुंचाने के लिए भी वैगन्स की जरूरत रहती है । मेरी कांस्टीटुएन्सी, जौनपुर में ग्रीन वेजिटेबल बहुत पैदा होती है लेकिन उसको बाहर भेजने के लिए वैगन्स की शार्टेज है । पिछले साल भी मैंने कहा था तो कह दिया गया था कि प्रोवाइड कर दिए है लेकिन जौनपुर के लिए वैगन्स प्रोवाइड नहीं किए गए । मैं मंत्री जी से जानना

चाहता हूं क्या वे जौनपुर में ग्रीन वेजिटेवल्स को बाहर भेजने के लिए जो वैगन्स की डिमांड है, उसको पूरा करेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : ग्रीन वेजिटेवल्स के लिए वैगन सप्लाई करने के लिए हम तैयार हैं। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने हमारे पास पत्र भी लिखा है, इसकी हम जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप हमदर्दी के साथ देखें। केला तो भगवान ने पत्तों में हलवा डाल के भेजा है, यह आम जनता के लिए है। दूसरे फलों के लिए भी आप देखें।

Excluding occupied areas of Jammu and Kashmir from the Map published in Indian Government Advertisement

+

*174. DR. SUBRAMANIAM SWAMY:

SHRI K. MALLANNA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item in Hindustan Times dated 21 September, 1982 that a map of India, published in an Indian Government advertisement in an international magazine, New York, excludes the Pakistan-occupied areas of Kashmir from it, although New Delhi continues to claim the areas as an integral part of the country.

(b) whether it is also a fact that the map published totally excluded the Pakistan-held areas of Kashmir from the Indian territory, although the Chinese-held areas are included; and

(c) if so, the reaction of the Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI A. A. RAHIM): (a) Yes, Sir. The *Scientific American* published a Special Report, as an advertisement section, on India in their August, 1982 issue. The map referred to was drawn by a cartographer commissioned by the editor of the Special Report. The map was not cleared by the Government of India nor by any official of the Government.

(b) Yes, Sir.

(c) The matter was immediately taken up with *Scientific American*, who have regretted what they call this unintentional error. They have assured us that they will be publishing a suitable apology and explanation in their November issue, which is the earliest possible opportunity for remedying the matter.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I regret to say that because of the Government's lack of clarity on the Kashmir question, lot of countries are publishing maps of India showing parts of Kashmir as missing.

I would like to know from the Government .....